भाषाका सवाल

रजि० नं० बी ४४४८
लाअिसेन्स नं० १५

हरिजनसेवक

दो आना

(संस्थापक : महात्मा गांधी)

भाग १९ सम्पादक : मगनभाई प्रभुदास देसाई अंक ३४

मुद्रक और प्रकाशक
जीवणजी डाह्याभाअी देसाअी
नवजीवन मुद्रणालय, अहमदाबाद–१४

अहमदाबाद, शनिवार, ता० २२ अक्तूबर, १९५५

वार्षिक मूल्य देशमें रु० ६
विदेशमें रु० ८; शि० १४

भय, असुरक्षितता और अनुशासनहीनता

प्रधानमंत्रीने कुछ दिन पहले दिल्लीमें अपना पार्लमेन्टरी काम-काज पूरा करके अेक हफ्तेके लिअे दक्षिण भारतका दौरा किया। जैसा कि अुन्होंने कहा, प्रधानमंत्रीके हस्बमामूल सरकारी काम-काजके बीच सुविधानुसार अवकाश मिलने पर वे अखिल भारतीय दौरे कर लेते हैं, जिनसे अुन्हें बड़ी प्रेरणा मिलती है। ये दौरे अुनके लिअे अेक प्रकारके आध्यात्मिक भोजन और टानिकका काम करते हैं। अिससे अुन्हें अपनी जनताके, जिसे वे हृदयसे प्रेम करते हैं और जिसके लिअे वे रातदिन काम करते हैं, सीधे संपर्कमें आनेका जरूरी मौका मिलता है। अुस संपर्कके जरिये नये भारतकी आशाओं, आकांक्षाओं और अुमंगोंका अुन्हें पता चलता है। अैसे ही मौकों पर वे जनताके सामने अपना हृदय अुंड़ेल कर रख देते हैं। लोगोंके साथ वे लगभग बोलकर विचार करते हैं, मानो लोगोंके साथ मिल कर — जिनकी अिच्छायें वे अैसे सभा-संमेलनोंके जरिये जानते हैं — वे अपने विचारों और योजनाओंको अनुकूल दिशा देनेका प्रयत्न करते हैं।

२ अक्तूबरको, महात्माजीकी जयन्तीके दिन, वे मद्रासमें थे। अिस स्मरणीय दिवसने अुनके मद्रासके महान भाषणके लिअे आध्यात्मिक भूमिका तैयार कर दी। हम जानते हैं कि दक्षिण भारत आजकल हिन्दी भाषा और स्कूलोंमें अुसके शिक्षणकी ओर विरोधकी भावनासे देख रहा है। प्रधानमंत्री अिस विषय पर भी बोले। अुनके भाषणका वह भाग अिसी अंकमें अन्यत्र दिया गया है।

अेक तरहसे अुन्होंने जो कुछ कहा वह नअी बात नहीं है। जबसे राष्ट्रपिताके नेतृत्वमें हिन्दी, भारतकी आन्तर-भाषा, के प्रचारका आन्दोलन शुरू हुआ, तबसे दक्षिण भारतकी सभाओंमें अुन्होंने भी अनेक अवसरों पर यह बात कही थी।

जवाहरलालजी आम तौर पर हमारी प्रजाके कामकाजमें और खास तौर पर विद्यार्थी-जगतमें आज अनुशासनकी जो बड़ी जरूरत मालूम होती है अुसके व्यापक संदर्भमें भाषाके प्रश्न पर बोले थे। जाहिर है कि हालमें ही अलाहाबाद विश्वविद्यालयको बन्द करनेकी दुःखद आवश्यकता अुनके दिमागको अुस समय परेशान कर रही थी। जैसा कि अुन्होंने कहा, वे नयी पीढ़ीमें जब यह सारी असभ्यता और अनुशासनहीनता देखते हैं, तब अुन्हें लगता है कि अिस देशका क्या होगा। और यह ठीक ही है। प्रधानमंत्रीने कहा कि वे भारतमें शिक्षणका स्तर गिरनेसे बड़े चिन्तित हैं। बेशक, यह हमारी नयी पीढ़ीके विकास और मानसिक स्वास्थ्यके बारेमें अेक अत्यंत खतरनाक लक्षण है।

अैसी स्थितिके कारणकी चर्चा करते हुअे प्रधानमंत्रीने कहा कि शिक्षणका स्तर गिरनेका अेक कारण है भाषाओंके प्रश्न पर फैला हुआ भारी भ्रम और गड़बड़ी। कोअी नहीं जानता कि कौनसी भाषा ठीकसे सीखी जाय और कौनसी नहीं सीखी जाय। अिसका नतीजा है कि विद्यार्थी प्रत्येक भाषासे बिलकुल अनजान रह जाते हैं! और अिस विषय पर वे विस्तारसे बोले, जिस पर हमें अपने राष्ट्रके अितिहास और विकासकी अिस मंजिल पर अधिकसे अधिक ध्यान देना चाहिये।

जैसा कि मैंने पहले कहा, अिस विषयकी चर्चा बिलकुल नयी नहीं है। लेकिन हम जानते हैं कि जब कोअी राष्ट्र अपने पुनर्निर्माणके प्रयत्नमें लगा होता है, तब अुसके कामकाजमें अैसे क्षण भी आते हैं जब दो और दो चार जैसी सादी और स्पष्ट बात भी बार बार कहनी और याद दिलानी होती है। भाषाका प्रश्न, खास करके आजकी स्थितिमें, हमारे लिअे अैसी ही अेक चीज है।

अिस अंकमें अन्यत्र अुद्धृत किये गये भाषणमें प्रधानमंत्रीने दक्षिणके लोगोंको यह विश्वास दिलाया कि हिन्दी भाषा, जो संविधानमें गिनाअी गअी हमारी १४ भाषाओंमें से अेक है, तामिल, तेलगू, गुजराती या मराठीसे 'अधिक राष्ट्रीय' नहीं है और वह अिस तरह किसी पर अूपरसे लादी नहीं जायगी कि हमारी प्रजाकी अन्य किसी भाषाके विकासके मार्गमें आवे।

जैसा कि हम जानते हैं, यह आश्वासन अिस विषय पर राष्ट्रपतिसे लेकर हमारे देशके लगभग सारे अुच्च शासकोंकी हालकी घोषणाओंका सामान्य स्वर रहा है। अुनकी मंशा देशके लोगोंको, खास करके अहिन्दी-भाषी लोगोंको, 'हिन्दी साम्राज्य-वाद' के नामसे पुकारी जानेवाली चीजके वाजिब डरके खिलाफ फिरसे विश्वास दिलानेकी है।

यह आश्वासन हिन्दी-भाषी और अहिन्दी-भाषी दोनों भागोंके लिअे विशेष अर्थ और महत्त्व रखता है। हिन्दी-भाषी प्रदेशोंको याद रखना चाहिये कि अुनकी भाषा दूसरी भारतीय या — जैसा कि प्रधानमंत्रीने अुचित रूपमें कहना शुरू किया है — राष्ट्रीय भाषाओंसे अधिक राष्ट्रीय नहीं है। अब यह बात स्पष्ट समझ ली जानी चाहिये कि अगर हमारी भारतीय भाषाओंका वर्णन करनेके लिअे 'प्रादेशिक' शब्दका अुपयोग करना ही हो तो यह विशेषण हिन्दीके लिअे भी अुतना ही लागू होता है जितना कि अुर्दू, तामिल, तेलगू, गुजराती, मराठी वगैराके लिअे। बेहतर तो यह होगा कि 'प्रादेशिक' शब्दका स्थान अब अधिक सत्य और अधिक आदरणीय 'राष्ट्रीय' शब्दको दे दिया जाय। संविधानकी आठवीं सूचीमें गिनाअी गअी सारी भाषायें भारतीय यानी राष्ट्रीय भाषायें हैं, और अिस तरह हमारे देशके कामकाजमें अुन्हें अेकसी मान्यता और आदर तथा बढ़ने और विकास करनेका समान अवसर मिलना चाहिये।

www.vinoba.in

लेकिन हम जानते हैं कि अितिहासने हमें बहुभाषी राष्ट्र बनाया है; हम फ्रान्स या जर्मनीकी तरह अेकभाषी राष्ट्र नहीं बन सकते। फिर भी लोगोंके परस्पर व्यवहारके लिअे अेक समान भाषा अपनाकर हम वह लाभ और सुविधा भी अुठा सकते हैं। अभी तक हम अैसी भाषाको 'राष्ट्रीय' कहते रहे; अब समय आ गया है कि हम देशके पुनर्निर्माणके समय अुसकी भाषाके स्वरूपके बारेमें सही विचारोंके अनुकूल नये शब्द गढ़ लें।

परस्पर व्यवहारकी समान भाषा वास्तवमें भारतकी आन्तर-भाषा है। अुसका विकास हमें संपूर्ण राष्ट्रके सम्मिलित प्रयत्नोंसे करना होगा। वह भारतकी समस्त भाषाओंकी मददसे बढ़ेगी, अपना विकास करेगी और समृद्ध बनेगी; और जहां कहीं जरूरी या वांछनीय होगा, वहां वह अपने शब्द-भंडारके लिअे न केवल संस्कृतसे बल्कि भारतकी सारी भाषाओंसे और यदि मैं कह सकूं तो दुनियाभरकी भाषाओंसे भी शब्द लेगी। हमारी यह आन्तर-भाषा हमारी अेक राष्ट्रीय आत्माको और दुनियाके राष्ट्रोंके बीच मैत्रीभावसे काम करनेवाले स्वतंत्र राष्ट्रके जन-जीवनके समस्त क्षेत्रोंमें किये जानेवाले समान प्रयत्नको व्यक्त करेगी। अैसा साहस हमारे प्राचीन राष्ट्रका अेक समान प्रयत्न होगा, जो अब आधुनिक जगतमें फिरसे अपना स्वतंत्र जीवन शुरू करता है। अैसा साहस शुरू करनेके लिअे मौजूदा परिस्थितिका यह तकाजा है कि प्रधानमंत्रीने जैसा आश्वासन दिया है, वैसा ही आश्वासन स्पष्ट शब्दोंमें सारे सम्बन्धित लोगोंकी ओरसे दिया जाय।

अिसलिअे प्रधानमंत्रीके आश्वासनका हम हृदयसे स्वागत करते हैं। अिस सम्बन्धमें मैं अेक-दो बातें और जोड़ना चाहूंगा। अिस सामान्य आश्वासनको अब कुछ कार्यका ठोस रूप देनेकी जरूरत है, जैसे स्पष्ट शब्दोंमें यह बता देना चाहिये कि हमारी सार्वजनिक प्रवृत्तियोंके कौनसे सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्रोंमें आन्तर-भाषा लादी नहीं जायगी और राष्ट्रीय भाषाओंको अपने अुचित और अधिकारपूर्ण स्थानसे हटायेगी नहीं? लोगोंके मनमें अिस बातका सच्चा डर है कि आया राज्योंको शिक्षा, शासन, न्याय, धारासभा वगैरा जैसे भीतरी कामकाजके लिअे हिन्दीके साथ —जो आन्तर-प्रान्तीय और अखिल भारतीय व्यवहारके लिअे वहां रहेगी ही— सुखद समन्वय करते हुअे अपनी राष्ट्रीय भाषाका आजादीसे अुपयोग करने दिया जायगा या नहीं। कमसे कम सरकारकी ओरसे अैसा कोअी कदम नहीं अुठाया जाना चाहिये, जो सारे अहिन्दी-भाषी प्रदेशोंके लोगोंके मनमें छिपे हुअे अिस डरको जगा दे या बढ़ा दे। अैसा डर आर्थिक और अन्य क्षेत्रोंके भविष्यके सम्बन्धमें फैली हुअी अनिश्चितताके साथ आज हमारे लोगोंके मनमें अेक प्रकारकी अरक्षितताका भाव पैदा करता है। मेरे खयालसे यह कारण वर्गों और विभिन्न भाषा-भाषी समूहोंके बीच तनाव और दुश्मनीकी भावना पैदा करता है, जो प्रधानमंत्रीके शब्दोंमें 'असभ्यता और अनुशासनहीनता' का रूप ले लेती है। यह बड़ी गंभीर चेतावनी है। हमें अच्छी तरह याद रखना चाहिये कि हमारी राष्ट्रीय अेकता और स्वतंत्रताके लिअे भी यह बहुत खतरनाक है।

१४-१०-'५५ मगनभाई देसाई
(अंग्रेजीसे)

राष्ट्रभाषा हिन्दुस्तानी

[दूसरा संस्करण]

लेखक: गांधीजी; अनु० काशिनाथ त्रिवेदी

कीमत १-८-० डाकखर्च ०-६-०

नवजीवन प्रकाशन मन्दिर, अहमदाबाद-१४

सामाजिक खर्च और राज्यसत्ता

अखबारोंसे पता चलता है कि लोग ज्ञातिभोज, विवाह-शादीमें बाजोंगाजोंकी धूमधाम वगैरा सामाजिक रीति-रिवाजोंमें अितना अधिक खर्च करते हैं कि अुसका बड़ा आंकड़ा सरकारकी निगाहमें आ गया है। मोटे अन्दाज परसे कहा जाता है कि अधिक नहीं तो लगभग ७०० करोड़ रुपये लोग हर साल अिन कामोंमें खर्च कर डालते हैं! हमारी राष्ट्रीय आय प्रति मनुष्य रु० २७५ मानी जाती है, जिसमें से प्रति मनुष्य लगभग रु० २० सामाजिक खर्चमें चले जाते हैं। अर्थात् कुल आयका लगभग ७ प्रतिशत यह खर्च आता है।

यह खर्च बहुत कहा जायगा, कम कहा जायगा या ठीक कहा जायगा, अिस प्रश्नमें यहां हम नहीं जायंगे। हमें यह मान लेना चाहिये कि अैसा थोड़ा-बहुत खर्च तो समाजमें होगा ही। अगर हमारी राष्ट्रीय आय न बढ़े, तो अुसका प्रतिशत अधिक जरूर लगेगा। सामाजिक कार्योंमें कुछ न कुछ रंग-राग तो सारी दुनियामें होता है। हमारे देशकी यह दशा है कि गरीबोंके घर अैसे मौकों पर ही थोड़ा-बहुत आनन्द-प्रमोद होता है। अुस पर सरकार अगर नियंत्रण या रोक लगाये तो वह ठीक नहीं कहा जायगा। फिर भी अितना तो निर्विवाद है कि अुस खर्चमें जो पागलपन या बुराअी है वह दूर होना चाहिये।

परंतु सरकारके अर्थ-मंत्रीकी अिसमें जो दिलचस्पी पैदा हुअी है वह दूसरे ही कारणसे है। मालूम होता है अुनके मनमें यह विचार आया है कि अैसे खर्च पर टैक्स लगाया जा सकता है! और योजना-कमीशनके लोगोंको लगता है कि यदि समाज-सुधारक थोड़ा जोर लगा कर अिस खर्चमें थोड़ी बचत करा दें तो योजना-संबंधी आर्थिक जरूरतें पूरी करनेमें हमें थोड़ी मदद हो जाय! अुन्हें अब हिसाब करने पर पता चला है कि पंचवर्षीय योजनाके खर्चका अन्दाज कूता जरूर गया है लेकिन वह खोखला है; अितनेसे सोचा हुआ कार्य पार नहीं पड़ सकेगा। और अिस अन्दाज जितना रुपया भी देशमें से येनकेन प्रकारेण खींचने पर भी पाना कठिन है। अिसलिअे अर्थ-मंत्री और योजना-मंत्री चारों तरफ नजर डालें यह स्वाभाविक है।

मुझे भी अैसा लगता है कि यह नजर अच्छी नहीं है। समाज-सुधारके फलस्वरूप लोग अपने रीति-रिवाजोंमें यदि परिवर्तन करें और खर्चमें बचत करें, तो वह रकम अुनके पास ही रहेगी और रहनी चाहिये। क्योंकि वह बचत आज तो अुनके परिवारके निर्वाहके लिअे ही जरूरी है। अिसके सिवा बिक्री-कर तो लिया ही जाता है। तब यह अतिरिक्त कर लेना ठीक नहीं होगा, वह नहीं लिया जा सकता।

परंतु मेरे कहनेका पाठक यह अर्थ न करें कि समाज-सुधार न किया जाय। सुधारका बहुत बड़ा काम आज हमारे समाजके सामने है। वह कानूनसे नहीं हो सकता। कर लगाकर या बारात वगैरामें भाग लेनेवालोंकी संख्या तय करके भी यह काम नहीं होना चाहिये। अिससे समाजमें कोअी सुधार नहीं होता, अुलटे सरकारी नियंत्रणों और प्रतिबंधोंसे अुसकी परेशानी ही बढ़ती है। सरकारी नौकरोंके लिअे रिश्वत लेनेकी गुंजाअिश बढ़ती है। सार यह कि अुससे कोअी लाभ समाजको नहीं होता।

सरकारी भोजों, पार्टियों वगैरा अनेक प्रकारके समारोहोंमें सरकार जो पैसा खर्च करती है, अुसे योजना-कमीशन बन्द करे। सरकार आज ठाटबाट और शान-शौकतके पीछे कम पैसा खर्च नहीं करती। अिसके सिवाय, व्यर्थके प्रचारके पीछे प्रत्येक सरकारी विभाग कुछ तो बिलकुल गैरजरूरी खर्च करता है, जिसे पागलपन ही कहा जायगा। अैसे अनेक खर्च सामने आयेंगे, जिनमें ध्यान देकर किफायतशारी और बचत करनेकी जरूरत है। अिसमें यदि सरकार लोगोंके सामने अुदाहरण रखे तो बहुत लाभ हो।

www.vinoba.in

सामाजिक खर्चोंके बारेमें गहराअीसे सोच-विचार कर नियंत्रण लगाने, काटकसर करने, तथा सुरुचि और विवेककी रक्षा करनेकी बहुत ज्यादा जरूरत है। यह काम जनता स्वयं अपने हाथमें ले, अैसी जाग्रति अुसमें आनी चाहिये। लेकिन यह भी जनताको ही करना होगा।

६–१०–'५५ मगनभाई देसाई

(गुजरातीसे)

आन्ध्रमें विनोबाके तीन दिन

आन्ध्रमें श्री गोरा, जो अपनेको नास्तिक या अनीश्वरवादी कहते हैं, और अुनके साथी भूदान-आन्दोलनमें शरीक हो गये हैं। आन्ध्रमें भूदानके मंच पर अिन अनीश्वरवादियोंके आनेसे सनातनी हिन्दुओंके अेक वर्गको तथा कांग्रेसी और समाजवादी पार्टीके राजनीतिक कार्यकर्ताओंको अनुमान लगाने और विरोध प्रकट करनेका मौका मिल गया। सनातनी अिसलिअे क्षुब्ध हो गये कि अुन्हें अिस बातका डर था कि ये लोग अनीश्वरवादके विचारोंका जनतामें प्रचार करेंगे, जब कि राजनीतिक दलोंको नये आनेवालोंकी नीयत पर ही शंका थी, क्योंकि अैसा कहा गया था कि अुनमें कुछ कम्युनिस्ट रह चुके लोग भी शामिल हैं। कुछ लोग तो अिन नये मित्रोंके प्रवेश पर रोक लगानेका सुझाव रखनेकी हद तक आगे बढ़ गये। अुन्होंने यह कहा बताया जाता है कि "अगर भूदान अिन अनीश्वरवादियों और भूतपूर्व कम्युनिस्टोंको गले लगानेके लिअे तैयार हो तो हमारा अुससे कोअी वास्ता नहीं।"

यह प्रश्न कार्यकर्ताओंकी अेक सभामें अेक भूदान-कार्यकर्ताने अुठाया, जो दुर्भाग्यसे अपनी बातकी पुष्टि आगंतुकोंके किसी आपत्तिजनक कार्यसे नहीं कर सके। श्रोताजन विनोबाके अुत्तरकी अुत्सुकतासे प्रतीक्षा कर रहे थे। बिनोबाने कार्यकर्ताकी बात हंसीमें टालते हुअे कहा कि अैसा डर रखनेका कोअी कारण नहीं है; अगर और जब कभी कोअी अैसी बात आपके देखनेमें आवे तो मेरे ध्यानमें लाअिये। लेकिन यह चीज अुन्होंने बिलकुल स्पष्ट कर दी कि मैं किसीको अपने पास आनेसे मना नहीं कर सकता। भूदान तो क्या, यह मेरे जीवनका ही नियम है।

यद्यपि श्रोताजन विनोबाके रुखको जानते थे और अिस मुद्दे पर गहराअीसे विचार करते मालूम नहीं हुअे, फिर भी मित्रोंने अपने बीच अिस दृष्टिकी वांछनीयता या अवांछनीयताकी चर्चा जरूर की। क्या भूदान या सर्वोदयने आज तक यह बात नहीं कही कि वे सब पार्टियों और सब लोगोंको अपना मानते हैं और किसी भी स्त्री या पुरुषको अिस ध्येयकी सेवा करनेसे वंचित नहीं रख सकते? अिसके सिवा, किसीकी नीयत पर शक कैसे किया जा सकता है, और क्यों करना चाहिये? और मान लो कि अुनमें से कुछ लोग परिस्थितियोंका लाभ अपनी विचार-धाराओंके प्रचारके लिअे अुठायें, तो अिससे वे सर्वोदयके अुद्देश्यको कैसे नुकसान पहुंचायेंगे, जिसे अपना निश्चित कार्य करना है? सर्वोदय कभी किसी विचार या संस्थाका विरोध करनेका दावा नहीं करता। वह अपने शुद्ध मूल्योंके बल पर खड़ा है, अिसीलिअे सारी दुनियामें अुसकी कदर होती है।

कांग्रेस अध्यक्षका सही रुख

प्रदेश कांग्रेस कमेटीके अध्यक्ष श्री सत्यनारायण राजुने, जो अिस सारी चर्चामें हाजिर रहे थे, समयानुकूल घोषणा की: "कांग्रेसने भूदानका अिजारा नहीं लिया है, और न अुसे लेना चाहिये। वह हमारा अेक सबसे महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम माना गया है, जिसे पहला स्थान दिया गया है। और हमसे आशा की जाती है कि भूदानको सफल बनानेके लिअे हम विनोबाजीके कार्यमें पूरा सहयोग दें। अिसी तरह हरअेकको अिस आन्दोलनमें शरीक होनेका अधिकार है, अिसलिअे कांग्रेसजन भूदानमें किसीके शरीक होने पर कोअी आपत्ति नहीं अुठा सकते, न अुन्हें अुठानी चाहिये। जो कोअी भूदानके कार्यमें लगे हों अुन सबके साथ अुन्हें खुशीसे सहयोग करना चाहिये।"

अितना ही नहीं, श्री राजुने विनोबाजीको अपनी प्रदेश कांग्रेस कमेटीके पूर्ण सहयोगका विश्वास दिलाया और यह जाहिर किया कि मैं और मेरे साथी आंध्रमें आपके मिशनको सफल बनानेमें कोअी कोशिश नहीं अुठा रखेंगे। यहां यह कहनेकी तो शायद ही जरूरत है कि श्री राजुके वक्तव्यसे जो अनुकूल प्रतिक्रिया पैदा हुअी अुसकी सबने कदर की। अुनके शब्दों पर देशभरके सामाजिक और राजनीतिक कार्यकर्ताओंको ध्यान देना चाहिये।

कार्यकर्ताओंके सामने किये गये अपने भाषणमें विनोबाजीने कहा कि लोग शिथिल भाषामें कहते हैं कि जैसे अेक बार मुसलमान और बादमें अंग्रेज हम पर शासन करते थे, वैसे ही अब कांग्रेस हम पर शासन करती है। विनोबाजीने अिस रुखके खिलाफ चेतावनी दी और यह बताया कि वर्तमान शासन कैसे लोगोंका शासन माना जाता है। अिसलिअे लोगोंकी मर्जीके खिलाफ अुन पर कोअी बात लादी नहीं जा सकती।

दूसरे, यह बात सबको स्पष्ट कर देनी चाहिये कि विनोबा या भूदान-आन्दोलनकी मंशा लोगोंसे जमीन हथियानेकी नहीं है। अिसके विपरीत विनोबा चाहते हैं कि लोग स्वेच्छासे, पूर्ण सद्-भावनासे और परस्पर सलाह-मशविरा करके ही अपने गांवके बेजमीन लोगोंको अपनी जमीनका हिस्सा दें; और अिस तरह गांवमें सरकारका राज्य नहीं बल्कि ग्रामराज्यकी स्थापना करें।

अन्तमें विनोबाने यह बात स्पष्ट की कि मैं जमीनकी समस्याकी अुतनी चिन्ता नहीं करता, जितनी कि लोगोंको जाग्रत और स्वाव-लंबी बनानेकी करता हूं, ताकि अपनी समस्यायें वे अपने बल पर और सहमतिसे हल कर सकें। भूदान अिसी दिशामें अेक प्रयोग है। भूदान ही जनशक्ति पैदा करनेमें बड़ा योग दे सकता है; और जनशक्ति ही ग्रामराज्यकी स्थापनाका अुद्देश्य पूरा कर सकती है, राजशक्ति नहीं। ग्रामराज्यकी स्थापना वर्तमान सर-कारकी शक्तिसे बाहरकी चीज है। कुछ लोगोंका यह खयाल है कि या तो खूनी क्रान्ति अिस ध्येयको सिद्ध कर सकती है या अैसी क्रान्तिके बाद आनेवाली सरकार। लेकिन अब यह चीज काफी साफ हो गअी है कि भूदान जैसी अहिंसक क्रान्तिसे ग्राम-राज्यका ध्येय कैसे सिद्ध हो सकता है।

विनोबाने कहा, बेशक आजकी सरकार जमीनकी अूंचीसे अूंची मर्यादा बांध सकती है। मुझे सचमुच आश्चर्य होता है कि कम्युनिस्ट मित्र भी आंध्रमें सिंचाअीवाली जमीनकी २० अेकड़की मर्यादा बांधनेकी हिमायत कैसे कर सके। अब यह अच्छी तरह मालूम हो गया है कि मर्यादा जमीनकी समस्या हल करनेमें बुरी तरह असफल रही है। क्योंकि जमींदारोंमें अितनी दूर-दर्शिता और बुद्धिमानी है कि कोअी कानून अुन पर असर करे अुसके पहले ही वे अपनी जमीनोंका अिन्तजाम कर सकते हैं। हैदराबादमें और देशके दूसरे भागोंमें अैसा ही हुआ है। और मान लें कि मर्यादा कारगर साबित होगी, लेकिन अुससे अितनी जमीन नहीं मिलेगी जो बेजमीनोंमें बांटनेके लिअे काफी हो। बंगालके बेजमीनोंमें बांटनेके लिअे २० से २५ लाख अेकड़ जमीनकी जरूरत है, जब कि वहांके मुख्यमंत्रीके कथनानुसार मर्यादा बांधनेसे केवल ४ लाख अेकड़ जमीन ही मिलेगी। मेरा अिरादा सरकारोंकी टीका करनेका नहीं है। मैं सिर्फ यही दिखाना चाहता हूं कि जनशक्ति सफल होती है, जब कि राज्यशक्ति असफल रहती है।

(अंग्रेजीसे) वामोदरदास मूंदड़ा

www.vinoba.in

हरिजनसेवक

२२ अक्तूबर १९५५

भाषाका सवाल

[श्री जवाहरलाल नेहरूके मद्रासमें दिये गये ता० २-१०-'५५ के भाषणसे]

अपने संविधानमें हमने भारतकी १२ या १३ भाषायें गिनायी हैं और अुन सबको भारतकी राष्ट्र-भाषायें कहा जा सकता है। अुनमें से कअी तो "आपकी अपनी श्रेष्ठ भाषा तामिलकी तरह बहुत पुरानी और महान हैं" (हर्ष-ध्वनि)। ये सब भाषायें बहुत सही अर्थमें राष्ट्र-भाषायें हैं। संविधानमें यह भी कहा गया है कि "हिन्दी अखिल भारतीय राजभाषा है और होनी चाहिये।" "लेकिन अिस कारण तामिल, गुजराती, मराठी या तेलगूसे हिन्दी ज्यादा राष्ट्रीय हो जाती है, अैसी बात नहीं है। अुसका केवल अितना ही मतलब है कि भारतकी राष्ट्रीय भाषाओंमें, कअी कारणोंसे हिन्दी अखिल भारतीय कार्योंके लिअे राजभाषाकी तरह स्वीकार किये जानेके लिअे सबसे ज्यादा आसान भाषा है। अन्यथा अुसमें दूसरी भाषाओंकी तुलनामें अैसी कोअी प्रमुखता नहीं है।"

श्री नेहरूने यह आश्वासन दिया कि "तामिल और हिन्दीमें कोअी विरोध नहीं है।" अुन्होंने कहा — अगर आप दूसरे देशोंमें जायं तो आप देखेंगे कि वहां हरअेक शिक्षित आदमी कम-से-कम दो और अकसर तीन भाषायें बहुत अच्छी तरह सीखता है और अिसके सिवा दो-तीन दूसरी भाषाओंकी मामूली जानकारी रखता है। अेक दूसरा सवाल अंग्रेजी भाषाके भविष्यका अुठता है। "लेकिन पहली चीज जो मैं चाहता हूं यह है कि आप याद रखें कि हिन्दी और तामिल या तेलगू या और किसी भाषामें किसी तरहका विरोध है, अैसी बात सोचना अेकदम निराधार है। तामिल अिस क्षेत्रकी अेक महान् भाषा है और मैं चाहता हूं कि अुत्तरके लोग अधिकाधिक संख्यामें तामिल सीखें। साथ ही यह भी जाहिर है कि सरकारी कार्योंके लिअे हमारी अेक सामान्य भाषा भी होनी चाहिये। नहीं तो भाषाओंकी अितनी दीवालें हमारे बीचमें आती हैं कि हमारा अेक-दूसरेसे व्यवहार करना असंभव हो जाता है। अिसीलिअे हिन्दी राजभाषा चुनी गयी है और कोअी दूसरी भाषा हमारे पास अैसी नहीं है जो यह काम कर सके। हिन्दी न तो बाहरसे लादी जानेवाली है और न वह किसी दूसरी भाषाके रास्तेमें आयगी। यह सोचना कि वह बाहरसे लादी जायगी बिलकुल ही गलत है। व्यवहारमें हम अैसा कोअी भी कदम नहीं अुठायेंगे जिससे हिन्दी न जाननेवाले लोगों पर — वे सरकारी नौकरियोंमें काम करते हों, या कहीं और — कोअी बोझ पड़े।"

"मुझे खेद है कि यहां मद्रास राज्यमें कुछ लोगोंने हिन्दीके खिलाफ आन्दोलन चलाया। अिस आन्दोलनका कोअी अर्थ नहीं है, क्योंकि कोअी भी हिन्दीको लोगों पर लादना नहीं चाहता। मुझे विश्वास है कि हिन्दीका ज्ञान हरअेकके लिअे हर तरहसे लाभकारी होगा, जैसे कि अंग्रेजीका ज्ञान भी मैं मानता हूं कि लाभकारी सिद्ध होगा। अब हम अिस अंग्रेजीके सवाल पर थोड़ा गौर करें। यह तो जाहिर है कि अंग्रेजी राष्ट्रभाषाकी तरह नहीं रह सकती। सामान्य जनताके लिअे विदेशी माध्यम नहीं चलाया जा सकता। लेकिन साथ ही मैं अिस बातको भी बिलकुल साफ कर देना चाहता हूं कि भारत और अुसके भावी विकासके लिअे यह चीज अच्छी नहीं होगी कि हम सारी अभारतीय भाषाओंसे नाता तोड़ लें, अुनकी बिलकुल अुपेक्षा करें। विदेशी भाषायें सीखना हमारे लिअे बहुत जरूरी है।

"यह विदेशी भाषा जिसे हम सीखें क्या हो, यह बात मैं लोगोंकी पसन्दगी पर छोड़ना चाहता हूं। लेकिन यह तो जाहिर है कि हमारे लिअे अंग्रेजी सबसे आसान विदेशी भाषा है; वह जर्मन, फ्रेंच रूसी, चीनी, स्पेनिश आदि दूसरी सब विदेशी भाषाओंसे ज्यादा सरल है। मैं अुम्मीद करता हूं कि हमारे लोग अिन तथा दूसरी विदेशी भाषाओंको सीखेंगे, क्योंकि अब विशाल दुनियामें हम अपना हिस्सा अदा कर रहे हैं। हमें विदेशी भाषा जाननेवाले नवयुवक चाहिये। हमें अैसे जानकार तैयार करना है; अपने वैदेशिक सेवा-तंत्रके लिअे हमें अैसे लोग सैकड़ों-हजारोंकी संख्यामें चाहिये।

"अिसके सिवा, विदेशी भाषाके ज्ञानके बिना कोअी विज्ञान नहीं सीख सकता, चाहे वह हिन्दी या तामिलका बहुत बड़ा विद्वान् क्यों न हो। हिन्दी या कोअी भी भारतीय भाषा विज्ञान सीखनेमें आज तो आपकी कोअी मदद नहीं कर सकती; हां, आगे चलकर करने लगेंगी। अुनमें वैज्ञानिक साहित्य नहीं है। और अभावकी स्थितिमें से कुछ भी पैदा नहीं किया जा सकता। भौतिक विज्ञान और रसायन-शास्त्रकी कुछ पाठ्य-पुस्तकोंका अनुवाद कर देने मात्रसे वैज्ञानिक साहित्यके अभावकी पूर्ति नहीं हो सकती। अिसलिअे विदेशी भाषाका ज्ञान तो जरूरी हो जाता है।

"स्पष्ट है कि अैसी हालतमें अंग्रेजीको, जिसे हम जानते हैं, भुलाना मूर्खता होगी। अंग्रेजी दुनियाकी महत्त्वपूर्ण भाषाओंमें से अेक और सबसे ज्यादा व्यापक ही नहीं है, कअी दृष्टियोंसे वह आज दुनियाकी सबसे महत्त्वपूर्ण भाषा है। अिसलिअे हमें अपना अंग्रेजीका — सही किस्मकी अंग्रेजीका, मामूली टूटी-फूटी अंग्रेजीका नहीं — पढ़ना-पढ़ाना जारी रखना है। अैसा मैं अिसलिअे कहता हूं कि अगर हम किसी विदेशी भाषासे पूरा परिचय नहीं रखेंगे तो हम अपने वैज्ञानिक और औद्योगिक कार्य अच्छी तरह नहीं कर सकेंगे।

"दुर्भाग्यसे, हम लोग कअी सौ सालों तक अपने घेरेके भीतर बन्द रहे हैं। अिसका अेक कारण तो हमारी भौगोलिक परिस्थिति थी — अुत्तरमें हिमालय और चारों ओर समुद्र। तो भी, जैसा कि आप जानते हैं, २००० या ३००० वर्ष पहले भारतीय लोग भारतकी सीमाओंके बाहर भी गये थे। अुन दिनों भारतीय लोग बाहर जानेसे डरते नहीं थे। अुन्हें साहससे प्रेम था। वह हमारे अितिहासका अेक प्राणवान् युग था। अुसके बाद वह युग आया जब कि हम लोग अधिकाधिक अपनी सीमाओंके अन्दर रहनेवाले बन गये। हमें अिस बातका भी पता नहीं रह गया कि भारतीयोंके सिवा और भी लोग दुनियामें हैं; बाहरी दुनियाका हमें कोअी ज्ञान नहीं रहा। हमें लगा कि हम तो स्वयंपूर्ण हैं। और अपने देशके अन्दर भी हमने अपनेको असंख्य जातियोंमें बांट लिया, छोटे-छोटे टुकड़े बना लिये और बीचमें दीवारें खड़ी कर दीं। तब अिसमें क्या आश्चर्य है कि हम गिर गये और गुलाम बन गये। तो आप देखते हैं कि अपनी ही सीमाओंके अन्दर बंद हो जानेसे राष्ट्रकी कैसी अवनति होती है।

"मैं आपको अिसकी याद अिसलिअे दिलाता हूं कि हमें अपने अितिहाससे तथा दूसरोंके अितिहास और अनुभवसे लाभ अुठाना है। अब हम आजाद हैं और यह आजादी हमें अैसे समय प्राप्त हुअी है जब कि दुनिया अधिकाधिक नजदीक आती जा रही है। वे सारी दीवालें, कुदरती दीवालें जो लोगोंका दूर आना-जाना रोकती थीं, अेकदम समाप्त हो गयी हैं। अैसी हालतमें अगर हम फिर अपने ही घरको दुनिया माननेवाली कूप-मण्डूक वृत्ति अपनायें तो वह अेक खतरनाक चीज होगी। तब हम प्रगतिकी दौड़में पीछे पड़ जायंगे। अिसलिअे हमें स्वतंत्र राष्ट्रकी दृष्टिका विकास करना है — यह दृष्टि विशाल दुनियाकी आधुनिक प्रवृत्तियोंके अनुकूल होनी चाहिये।

www.vinoba.in

"भारतमें अिस समय अेकता और प्रगतिकी ओर ले जानेवाली बलवान् प्रवृत्तियां काम कर रही हैं। कुछ प्रवृत्तियां अैसी भी हैं जो अिस अेकताको तोड़ती हैं और बिखेरती हैं। हममें से कुछ लोग अिन प्रवृत्तियोंकी अुपेक्षा करते हैं। लेकिन मेरा खयाल है कि हमें अुनकी अुपेक्षा नहीं करना चाहिये। हमें तो हमेशा सजग रहना है। भारतीय मानसमें यह विभाजनकी — विघटनकी प्रवृत्ति बहुत समयसे चली आ रही है। प्रान्तीय, भाषा-संबंधी और अन्य अनेक प्रभाव हैं जो हमें हमेशा अेक-दूसरेसे अलग करनेकी दिशामें अपना जोर लगाते रहते हैं। अिसलिअे हमें बहुत सजग रहना है। क्योंकि अेक बात निश्चित है कि भारतकी प्रगति अुसकी अेकता पर, हर-अेक परिस्थितिमें छत्तीस करोड़ भारतीयोंके साथ मिलकर रहने और काम करने पर निर्भर करती है। यह अेक बुनियादी बात है। जिस क्षण अैसा मालूम हो कि हम अिस अेकताकी, साथ मिलकर रहने और काम करनेकी बुनियादी आवश्यकताकी मांग पूरी नहीं कर रहे हैं, अुसी क्षण यह निश्चित समझना चाहिये कि हम लोग कितने ही कुशल या बुद्धिमान् क्यों न हों, हम आगे नहीं बढ़ सकेंगे। यदि हम अिस अेकताकी रक्षा नहीं करते हैं तो राष्ट्रके नाते हम गिरेंगे।" *

(अंग्रेजीसे)

खादी और ग्रामोद्योगोंका अर्थशास्त्र

[ता० ७–१०–'५५ को अहमदाबाद रेडियो पर किया गया वायु-प्रवचन अुसकी अिजाजतसे यहां दिया गया है।]

ये दिन गांधी-जयंती सप्ताहके हैं। अिस मौके पर गांधीजीके अतिप्रिय खादी और ग्रामोद्योगोंके अर्थशास्त्रकी चर्चा करनेका प्रसंग आनन्ददायक कहा जायगा। गांधीजी खादी और ग्रामोद्योगोंको हमारे देशके आर्थिक पुनर्निर्माणका रामबाण अुपाय मानते थे। देशके लाखों गांवोंमें फैली हुअी हमारी गरीबसे गरीब और अुपेक्षित विशाल जनताके बीच घूमते-घूमते अुन्हें यह सत्य प्राप्त हुआ था। अुस प्रजाको वे दरिद्रनारायण कहते थे। अिसीसे वे कहते थे कि अिस दरिद्रनारायणकी सेवा और आराधना खादी और ग्रामोद्योगोंके बिना नहीं हो सकती, और यह सेवा भारत अगर नहीं करेगा तो हमारे यहां सच्चे स्वराज्यका सूर्योदय भी नहीं होगा।

अुन्होंने वर्षों पहले यह नम्र दावा किया था कि हम अिन अुद्योगोंका सहारा लिये बिना शायद ही देशकी बेकारी दूर कर सकेंगे। वह बात आज भी अुतनी ही सच मालूम होती है। हमारे देशमें बेकारीका कोअी पार नहीं है। कोअी बड़ा अर्थ-शास्त्री भी हिम्मतके साथ यह नहीं कह सकता कि बेकारोंकी संख्या अितनी या अुतनी है! सरकारके पास भी अिसके निश्चित आंकड़े नहीं हैं। बात तो यह है कि जहां पूर्ण बेकारी या अर्ध-बेकारी ही देशके अुद्योग-धंधोंकी करुण दशा हो, वहां आंकड़ा-शास्त्री भी किस तरह हिसाब लगायें! कुछ अलग अलग नमूनेके क्षेत्रोंको लेकर वे हिसाब लगाते हैं और बेकारीका प्रकार और अुसका अन्दाज लगाते हैं। अिससे भी यही मालूम होता है कि बेकारी मानो भारतके रोजगार-धंधेकी दशाको लगी हुअी सील जैसी है। अिस सीलको खोदकर हटाया नहीं गया तो हमारे देशके रोजगार-धंधेका मकान धीरे-धीरे टूटने और गिरने लगेगा, यह साफ है।

अतः अिसका अिलाज किये बिना हमारा काम नहीं चल सकेगा। अब तो हमारे अर्थशास्त्री भी यह बात स्वीकार करने लगे हैं कि वह अिलाज आज भी खादी और विविध ग्रामोद्योग ही हैं। अिसीलिअे अिन अुद्योगोंको दूसरी पंचवर्षीय योजनामें आदरका स्थान प्राप्त हो सका है। खादी और ग्रामोद्योगोंके अर्थशास्त्रकी अनोखी शक्तिको बतानेके लिअे अिससे बेहतर प्रमाण और कौनसा मिल सकता है?

खादी और सारे ग्रामोद्योग मुख्यतः हाथ-अुद्योग हैं। अिसका अर्थ यह है कि मनुष्य अपने हाथोंका अुपयोग करके और अच्छी तरह काम देनेवाले तरह तरहके औजारों द्वारा ये अुद्योग चला सकता है। अिसके लिअे अुसे जो कच्चा माल चाहिये, वह अपने आस-पास होनेवाली विपुल पैदावारमें से प्राप्त कर सकता है। अिसके लिअे अुसे बहुत बड़ी पूंजीकी जरूरत नहीं होती। और अुसका बनाया हुआ माल अैसा होता है, जो आसपासके लोगोंकी जरूरतका होता है — अर्थात् वह जहांका वहीं खप सकता है।

अिसके अलावा, अैसे अुद्योग चलानेमें बड़े शहरों, अुनकी अंधेरी झोंपड़ियों और गन्दगी, तथा शहरकी दूसरी अनिवार्य पीड़ायें भोगनी नहीं पड़तीं। क्योंकि हाथ-अुद्योग होनेके साथ ही ये अुद्योग ग्रामोद्योग और गृह-अुद्योग भी हैं। अर्थात् अुनका संगठन अत्यंत सादगीसे गांवके घरोंमें ही किया जा सकता है।

फिर अुन्हें चलानेके लिअे आवश्यक कुशलता और कारीगरीका विचार करें तो वह भी बहुत सादी और सुन्दर होती है। कारीगर अुनमें अपना कला-कौशल अुंड़ेल देनेका सर्जनात्मक आनन्द ले सकता है। अुसमें शरीरकी सारी अिन्द्रियोंका पूर्ण अुपयोग होता है। अिस कारणसे यंत्रों पर करनी पड़ती अेकसी क्रिया जैसी थकावट, अुकताहट और मानसिक अशांति अुत्पन्न करती है, वैसा हाथ-अुद्योगों और गृह-अुद्योगोंमें नहीं होता। ये अुद्योग गृह-अुद्योग हैं, अिसलिअे अुनमें अेक विशेष आनन्ददायी गति और सन्तोषजनक परिश्रम होता है, जिसके कारण ये अुद्योग चलाने-वालोंमें शहरी मजदूरोंके जैसी कृत्रिम और समाजको हानि पहुंचाने-वाली मानसिक भूख और आधि-व्याधियां पैदा नहीं होतीं। अिन अुद्योगोंके कारण लोगोंकी समाज-वृत्ति और कुटुम्ब-भावना जैसी हितकारी भावनाओंका पोषक वातावरण बना रहता है। हमारे देशकी ग्रामीण संस्कृतिके लिअे यह सुन्दर चीज है।

अिसके साथ ही गांधीजीने अिन अुद्योगोंके अर्थशास्त्रके बारेमें अेक अैसी ही महान क्रान्तिकारी बात और कही थी। अुन्होंने कहा था कि अिन हाथ-अुद्योगों और ग्रामोद्योगोंमें से अनुकूल अुद्योग चुनकर यदि हम शालाओंमें अपने बच्चोंको समझपूर्वक करना सिखायें, तो अुनके अनुबंधमें अुन्हें अुत्तम ढंगसे शिक्षण भी दिया जा सकता है। आजकी शिक्षण-पद्धतिके कारण हमारे मनोंमें शरीर-श्रमके बारेमें जो अरुचि या तिरस्कारका भाव घुस गया है वह अिस नयी शिक्षण-पद्धतिके जरिये दूर होगा। और हम बालकोंकी शिक्षाकी पद्धतिको भी अेकदम अुत्पादक कार्य द्वारा शिक्षणके सर्वमान्य सिद्धान्तके आधार पर रख देंगे। अुससे अुपयोगी चीजें तैयार होंगी, यह भी कोअी छोटी बात नहीं है। अुसका हमारे आर्थिक जीवन पर भी असर होगा। अिस तरह अिन अुद्योगोंका असर केवल आर्थिक ही नहीं होता; वे हमारे समग्र जीवनके विविध पहलुओं पर भी अच्छा असर करनेवाले हैं। अुनके अर्थशास्त्रसे अनर्थ नहीं होता; अुनके विकासके लिअे जो भी कार्य किया जाय वह पुण्य कार्य ही होगा, अैसे मंगल और हितकारी वे हैं।

तो फिर सवाल यह अुठता है कि वे चलते क्यों नहीं? अुन्हें लोग अपनाते क्यों नहीं?

यह भी कहा जाता है कि अिन अुद्योगोंका माल महंगा पड़ता है, और अिसमें शंका है कि वह अच्छा, सुघड़ और टिकाअू होगा या नहीं।

अिन सवालोंका पूरी तरह जवाब देना हो तो भारतके दो-तीन सदियोंके आर्थिक और औद्योगिक अितिहासमें जाना होगा। अिसके लिअे यहां गुंजाअिश नहीं है। अिन अुद्योगोंका माल अच्छा

* ता० ३–१०–'५५ के 'हिन्दू' से अुद्धृत।

www.vinoba.in

और सुन्दर जरूर बनाया जा सकता है। अुसे बनानेवालोंको अुसमें लाभ दिखाअी दे अैसी परिस्थिति और आर्थिक हवा स्वराज्य सरकार पैदा कर सके तो यह आसानीसे हो सकता है। अर्थ-तंत्रको व्यवस्थित करके ग्रामोद्योगोंके मालको सस्ता भी बनाया जा सकता है। परन्तु बड़ी कठिनाअी तो अिस सम्बन्धमें दूसरी ही है।

सब कोअी जानते हैं कि जीवनकी जरूरतें पूरी करनेवाली सारी चीजें, जिन्हें हम घरोंमें पैदा करते थे, धीरे-धीरे यंत्रोद्योगोंसे और भाप-बिजलीकी शक्तिसे बनने लगी हैं। अिससे लोग बेकार बन गये, यंत्रोंका माल काममें लेनेकी हमें आदत पड़ गअी, अुसकी रुचि बढ़ी और अिस तरह जनताके श्रमका शोषण करके यंत्रोंके मालकी कीमत नीचे अुतारनेका नया अर्थशास्त्र, पैसाशास्त्र और राज्यशास्त्र जगतमें आज पैदा हुआ है। अिससे न केवल बेकारी ही फैली, बल्कि प्रत्यक्ष दिखाअी न देनेवाले सूक्ष्म शोषणके अनेक कारण भी समाजमें पैदा हो गये हैं।

यह नया अुद्योगशास्त्र और अर्थशास्त्र आज विज्ञानके नाम पर आदर पाता है। सभ्य मानी जानेवाली दुनियाका प्रवाह अुसकी ओर बह रहा है। अुसका प्रभाव हमारे शिक्षित और धनवान वर्गोंके मन पर है। और समाजका तो नियम ही है कि — 'महाजनो येन गतः स पन्थाः'।

यह सब समझकर आज हमारे शासक अब अिस निर्णय पर आये हैं कि लोगोंमें फैली हुअी बेकारी तो दूर करनी ही चाहिये और देशमें आर्थिक स्वावलंबन लाना ही पड़ेगा। अन्यथा सब सुखपूर्वक रोटी कमा सकें, अैसी अवस्था नहीं पैदा की जा सकती; और यदि अैसी अवस्था पैदा नहीं की जा सकती तो हमारी स्वतंत्रता भी टिक नहीं सकती। अिसलिअे यदि लोग अपने प्रतिदिनके व्यवहारकी घर-गृहस्थीके अुपयोगकी वस्तुअें यथासंभव हाथ-अुद्योग या ग्रामोद्योगसे बनावें तो देशमें पड़ी हुअी अपार श्रम-रूपी पूंजी काममें आ जाय। अिस तरह पैदा होनेवाले मालके साथ यंत्र अथवा कारखानोंमें बननेवाले मालको प्रतियोगितामें नहीं अुतरना चाहिये। अिसका यह अर्थ नहीं कि यंत्रों अथवा कारखानोंमें कोअी काम नहीं होगा। देशको बड़े-बड़े यंत्रों और औजारों, लोहा, रेलवेका सामान, मोटरें, बिजलीका सामान आदि वस्तुओंकी जरूरत तो है ही। ये वस्तुअें कारखानोंमें ही बन सकती हैं। देशके कारखानोंको अिस प्रकारके कामोंमें लगना चाहिये। अुनमें से कुछ सरकार प्रजाके पैसेसे खड़े करे और कुछ खानगी अुद्योगपति चाहें तो वे खड़े करें।

अिस तरह हमारे देशमें अुद्योग-धंधोंका जो नकशा बन रहा है अुसमें हम आसानीसे देख सकते हैं कि खादी और अन्य ग्रामोद्योगोंका सर्वसामान्य प्रजाकीय या राष्ट्रीय महत्त्व है। अुनके क्षेत्रका विस्तार सबसे बड़ा है। खेती और ये अुद्योग मिलकर देशके कुल धनका लगभग तीन-चौथाअी भाग पैदा करते हैं। अुसमें मानव-बल प्रायः अिसी प्रमाणमें लग जाता है। अिसलिअे यदि अिन अुद्योगोंको अपने पांवों पर अिस तरह खड़ा कर दिया जाय कि लोग अुन्हें आत्मसम्मानपूर्वक कर सकें तो हमने भारतकी औद्योगिक नवरचनाकी गंगा नहा ली, अैसा अवश्य कहा जा सकेगा। यह काम अेक महान सामाजिक क्रान्ति कर डालेगा।

दूसरा क्षेत्र बड़े-बड़े सरकारी अुद्योग-धंधोंका है, जिन्हें आज पंचवर्षीय योजनामें मुख्य स्थान दिया गया है।

अुसके बाद तीसरा क्षेत्र खानगी अुद्योगपतियोंके धंधोंका आता है। अुनके नियमनके लिअे भी अुपयुक्त कानून सोचे जा रहे हैं।

अैसा करके हम राष्ट्रकी अपार श्रम-पूंजीको, जो धन-पूंजी हम पैदा करते हैं अुसे तथा स्वराज्य-सत्ता और सरकारी पैसेको अेक ही योजनामें बांधकर देशकी नयी अर्थ-रचनाका निर्माण करनेकी ओर बढ़ रहे हैं। अिस कार्यक्रममें खादी और ग्रामोद्योग अग्रस्थानमें हैं। वे हमारे सच्चे राष्ट्रीय अुद्योग हैं। अुन्हें चालू रखकर ही हम सच्चे आर्थिक स्वराज्य तथा शांति और प्रेमसे युक्त अेक सहयोगी राष्ट्र-कुटुंबकी रचना कर सकेंगे। गांधी-जयंतीके अिस सप्ताहमें हम सब अिस नवरचनामें मदद करनेका संकल्प करके कृतार्थ बनें और राष्ट्र-पिताका ऋण चुकायें।

५–१०–'५५ मगनभाअी देसाअी

(गुजरातीसे)

हाथ-कुटाअीका अुद्योग

भारत जैसे कृषि-प्रधान देशमें ३७ प्रतिशत जमीनमें धानकी खेती होती है और देशमें अुत्पन्न होनेवाले धानमें से ४५ प्रतिशत चावल होता है। अिसके सिवाय, चावल देशके विशाल जनसमुदायकी अेक मुख्य खुराक है। वह ८० प्रतिशत कैलोरीकी पूर्ति करता है। और प्रति मनुष्य अधिकसे अधिक कैलोरीकी पूर्ति करनेमें चावलका खाद्यान्नमें अूंचा स्थान है।

अिन सब बातोंका खयाल करके धानकी हाथ-कुटाअीका अुद्योग कितना व्यापक, आवश्यक और महत्त्वपूर्ण है, अिसका विचार करना चाहिये। अिसके लिअे भारत-सरकारने अक्तूबर १९५४ में चावल हाथ-कुटाअी कमेटीकी रचना की थी।

वह कमेटी अपनी विस्तृत जांचके बाद नीचेके निर्णयों पर पहुंची थी:

१. १९५० की गणनाके अनुसार भारतमें फैक्टरी अेक्टके मुताबिक रजिस्टर की गअी चावल-कुटाअीकी १,४२४ मिलें हैं और अुनमें ५.९८ करोड़की पूंजी लगी हुअी है। विभिन्न प्रकारकी हलर मिलोंकी संख्या बताना कठिन है, क्योंकि वे देशके कोने-कोनेमें फैली हुअी हैं। अैसी बड़ी मिल खड़ी करनेके लिअे २० से ३० हजार रुपयेकी यंत्र-सामग्री जरूरी होती है। अैसी अेक मिल खोलनेसे ५०० हाथ-कुटाअी करनेवाले मजदूर और छोटी हलर मिल खोलनेसे ४० मजदूर बेकार बनते हैं।

२. आज हाथसे सारे देशमें ६५ प्रतिशत धानकी कुटाअी होती है, जब कि मिलों द्वारा ३५ प्रतिशत धान कूटा जाता है। सारी दृष्टियोंसे विचार करने पर हमें अिस अुद्योगका यंत्रीकरण करनेका अेक भी कारण मालूम नहीं होता। अुलटे, हकीकतें यह बताती हैं कि यह अुद्योग पूर्णतः ग्रामोद्योगके पैमाने पर ही चलना चाहिये।

३. अ० भा० खादी और ग्रामोद्योग बोर्डने अिस संबंधमें जो जांच हाथमें ली थी, अुसके आंकड़ोंके अनुसार मिल-कुटाअीकी अपेक्षा हाथ-कुटाअीसे ३.८ प्रतिशत अधिक चावल मिलता है। अिस तरह सम्पूर्ण देशका विचार करें तो अिस राष्ट्रीय संपत्तिका यह बिगाड़ तुरन्त रोका जाना चाहिये।

४. पोषक तत्त्वोंकी दृष्टिसे विचार करें तो चावलमें प्रोटीन, खनिज द्रव्य और विटामिन बी वगैरा तत्त्व होते हैं। और विटामिन बी, चावलमें पाया जानेवाला अत्यन्त महत्त्वपूर्ण तत्त्व है। यह तत्त्व मिल-कुटाअीसे नष्ट हो जाता है, जिसके फलस्वरूप 'बेरी-बेरी' नामक रोग होता है। अिस रोगको रोकनेके लिअे मलाया, फिलिपाअिन्स वगैरा देशोंमें यह तत्त्व बाहरसे चावलोंमें जोड़नेके प्रयत्न किये जाते हैं। हमारे देशमें भी भारतीय डॉक्टरी संशोधन कमेटीकी धान-संरक्षण कमेटी अिस सारे प्रश्न पर विचार करके अिस निर्णय पर पहुंची है कि हमारे देशमें हाथ-कुटाअीकी संभावना होनेसे तथा अुसमें विटामिन बी, सुरक्षित रहनेके कारण बाहरसे यह तत्त्व जोड़नेकी आवश्यकता नहीं है।

लीग ऑफ नेशन्सकी पूर्वीय देशोंसे संबंध रखनेवाली आन्तर-सरकारी परिषद्ने १९३७ में जावामें अेक प्रस्ताव पास करके

www.vinoba.in

आग्रहपूर्वक यह सिफारिश की थी कि कम कूटे हुअे (हाथ-कुटाअीके) चावल ही सरकारोंको अपनी प्रजाको देने चाहिये तथा प्रचार और शिक्षा द्वारा अैसे चावलोंको अधिक लोकप्रिय बनानेके प्रयत्न बढ़ाने चाहिये।

अमेरिकाकी राष्ट्रीय संशोधन कमेटीके खुराक और पोषण विषयक बोर्डने भी बिना पालिशवाले चावलके व्यापारके विकासकी सूचना की है। संयुक्त राष्ट्रसंघकी खुराक और खेतीबाड़ी विषयक संस्थाकी पोषण-संबंधी कमेटीने कहा है कि १ ग्राम संपूर्ण चावलमें अधिक नहीं तो १.३ माअीकोग्राम विटामिन बी, अवश्य होना चाहिये। अिसके सुरक्षित रहनेका आधार चावलकी कुटाअीकी मात्रा पर रहता है।

भारतके खेतीवाड़ी और खुराक विभागने निष्णातोंके साथ चर्चा करनेके बाद अैसा निर्णय किया था कि ५ प्रतिशत भूसी निकाली जाय तब तक चावल खाद्यान्नके रूपमें स्वीकार करने लायक होते हैं। भारत-सरकारका २३ नंबरका हेल्थ बुलेटीन साफ बताता है कि पोषणकी दृष्टिसे हाथ-कुटाअीके चावल अुत्तम होते हैं।

५. हाथ-कुटाअीसे निकलनेवाली भूसीमें छिलके कम मात्रामें होते हैं, अिसलिअे वह ढोरोंके लिअे अुत्तम खुराकका काम करती है। मिल-कुटाअीमें ये छिलेके भी पिस जाते हैं अिसलिअे भूसीके साथ ढोरोंके पेटमें चले जाते हैं और अुन्हें नुकसान पहुंचाते हैं।

६. सैद्धान्तिक पहलूसे देखें तो नैसर्गिक शक्तिसे चलनेवाली मिलोंके कारण अुद्योगका केन्द्रीकरण हो गया है और वर्ग खड़े हो गये हैं। और अुसका परिणाम आन्तर-राष्ट्रीय क्षेत्रमें बाजारोंकी खोज, होड़, साम्राज्यवाद और युद्धके रूपमें आया है।

७. कामधंधेकी दृष्टिसे देखा जाय तो भारत-सरकारके मजदूर-विभागने १९५२ में जो जांच कराअी थी, अुसके अनुसार ७८.८ प्रतिशत खेती-मजदूरोंके पास दूसरा कोअी अतिरिक्त धंधा नहीं है।

दूसरे, पूरे कामधंधेका विचार किया जाय तो गांवोंमें स्त्रियोंका अैसा बड़ा वर्ग है जिसे कुछ काम मिलना चाहिये।

अिस तरह सारी दृष्टियोंसे विचार करते हुअे यह बात स्पष्ट हो जाती है कि चावलकी मिल-कुटाअी किसी तरह लाभदायी और हाथ-कुटाअीसे अधिक अुपयोगी नहीं है। तब प्रश्न यही रह जाता है कि अिस अुद्योगका विकास किस तरह किया जाय। अथवा आज मिलोंमें जितना धान कूटा जाता है, अुतना ही हाथसे कूटा जा सके, अिसके लिअे क्या कदम अुठाये जायं?

अिसके लिअे धान हाथ-कुटाअी कमेटीने नीचेकी सिफारिशें और सूचनायें की हैं:

१. हाथ-कुटाअीके लिअे सारे देशमें नीचेके साधनोंका अुपयोग किया जाता है:—

साधन	कीमत	कुटाअी
अूखल-मूसल	१० रु०	प्रतिदिन १ मन
लकड़ेकी चक्की	२० रु०	प्रतिघंटे १ से १।। मन
पत्थरकी चक्की	४० रु०	" २ से २।। मन
मिट्टीकी चक्की	कुछ नहीं	प्रतिदिन १। मन
ढेंकी	३० से ४० रु०	" ५ मन
मछलीपट्टम चक्की	७०० रु०	" २० मन

खादी और ग्रामोद्योग बोर्डने अिन सबमें से पत्थरकी चक्की और ढेंकीका व्यापारिक पैमाने पर अुत्पादन करके गांवोंमें प्रचलित करनेका सोचा है।

२. अेक भी नअी मिल खुलने न दी जाय और वर्तमान मिलोंकी अुत्पादन-शक्ति बढ़ने न दी जाय। वर्तमान मिलोंके लिअे दिनमें केवल ६ घंटे काम करना अनिवार्य कर दिया जाय। गांवोंके पानीके अेंजिनोंके साथ चलनेवाली हुलर मिलोंको बन्द कराया जाय।

३. केवल विदेशोंमें भेजनेके लिअे ही धान कूटनेकी अिजाजत मिलोंको दी जाय। अैसा अुत्पादन सरकारकी निगरानीमें और मंजूरीसे हो। वह भी शेलर मिलों द्वारा ही; हुलर मिलों द्वारा हरगिज नहीं।

४. मिल-कुटाअीके चावल पर प्रति मन ०–६–० का सेस डाला जाय और वह रकम हाथ-कुटाअीकी शोध और राहतके लिअे अुपयोगमें ली जाय। अभी हाथ-कुटाअीके लिअे ०–६–० प्रति मनकी जो राहत दी जाती है, अुसे बढ़ा कर ०–८–० कर दिया जाय और वह स्वीकृत सहकारी केन्द्रों द्वारा दी जाय।

हाथ-कुटाअीके चावलको बिक्री-करसे मुक्त किया जाय। सरकार हाथ-कुटाअीके चावल ही खरीदनेका आग्रह रखकर अपने सारे क्षेत्रोंमें अुन्हींका अुपयोग करे।

५. राज्यकी सरकारें अिस अुद्योगको व्यवस्थित बनानेके लिअे कदम अुठायें, जिससे थोड़े समयमें वह मिलोंकी जगह ले सके। अुसे व्यवस्थित बनाते समय गावोंमें लोगोंको अधिक काम मिलनेकी बातको ध्यानमें रखा जाय और सहकारी आधार पर अुसका विकास करनेके लिअे सरकारें अगले पांच वर्षके लिअे अेक योजना तैयार करें। और प्रति वर्ष अुसकी सफलताओंका अवलोकन करें।

६. सारे साधनोंकी सहायता लेकर विविध विकास-केन्द्रों और समाज-सेवाके सरकारी क्षेत्रोंमें हाथ-कुटाअीके चावलके पोषण-संबंधी महत्त्व, अुसमें निहित अधिक रोजीकी संभावना तथा अुस चावलको रांधनेकी सही रीतिका खूब प्रचार किया जाय।

अिन सूचनाओंको अमलमें लानेके लिअे खादी और ग्रामोद्योग बोर्डने दूसरी पंचवर्षीय योजनामें समावेश करनेके लिअे हाथ-कुटाअी अुद्योगके संबंधमें नीचेका कार्यक्रम सुझाया है:

(१) अिस समय मिलों द्वारा १ करोड़ ४० लाख टन धान कूटा जाता है। अुसे १९६०-६१ तक हाथ-कुटाअीके मातहत लाया जाय।

(२) मिल पर प्रति टन रु० १०–८–० का सेस डाला जाय। १ करोड़ ४० लाख टनमें से ४० लाख टनको कर वसूल करनेकी कठिनाअीको ध्यानमें रखकर छोड़ दें, तो भी बाकीके धानसे अूपरके हिसाबसे योजनाके दौरानमें ३१.५० करोड़ रुपये अिकट्ठे हो सकते हैं।

(३) अगले पांच वर्षोंमें १.७ लाख चक्कियां और ८ लाख ढेकियां हाथ-कुटाअी करनेवालोंको मुहैया करनी हैं। अिनकी कीमतमें ७५ प्रतिशत राहत दें तो अुसमें ३.४७ करोड़ रुपये खर्च होंगे।

अिसके सिवाय, हाथ-कुटाअीके चावल पर प्रति टन रु० १४ अथवा प्रति बंगाली मन पर जो ०–८–० अुत्पादन-राहत दी जायगी अुसमें २३.५५ करोड़ रुपये खर्च होंगे। अिस प्रकार कुल राहत २७ करोड़ रुपये तक जायगी।

(४) फिर भी जो ४.५ करोड़ रुपये बचेंगे, वे अिस अुद्योगके लिअे खड़े किये जानेवाले तंत्र और कार्यकर्ताओंकी तालीममें खर्च होंगे। साथ ही, हाथ-कुटाअी करनेवालोंको साधन खरीदनेके लिअे २५ प्रतिशत कर्जके रूपमें दिये जा सकेंगे।

(५) योजनाके अंतिम वर्षमें अिस अुद्योग द्वारा प्रति बंगाली मन १ रुपया कुटाअीके हिसाबसे २४.५ लाख लोगोंको सालमें १५० दिनका काम मिलेगा। तथा ग्रामप्रजामें मजदूरीके रूपमें ५७.४ करोड़ रुपये बंटेंगे। अिसके सिवाय, हाथ-कुटाअीके साधन बनानेमें भी लगभग ३,००० आदमियोंको रोजी मिलेगी।

अगर सच्चे दिलसे अिस कार्यक्रम पर अमल किया जाय तो बेकारीका प्रश्न हल होनेमें बड़ी मदद मिलेगी और मिल-कुटाअी द्वारा राष्ट्रीय संपत्तिका जो बिगाड़ हो रहा है वह भी रुकेगा।

(गुजरातीसे) वि०

www.vinoba.in

कल्याण-राज्य बनाम सर्वोदय-राज्य

१

"प्रत्येक व्यक्तिको अपने तथा कुटुम्बियोंके स्वास्थ्य और सुखके लिअे — जिसमें अन्न, वस्त्र, घर, डॉक्टरी मदद तथा आवश्यक सामाजिक सेवायें शामिल हैं — पर्याप्त जीवन-मानका हक है; अिसी तरह अुसे बेकारी, बीमारी, पंगुता, वैधव्य, बुढ़ापा या अुसके वशके बाहरकी परिस्थितियोंमें जीविकाके अभावकी दूसरी किसी दशामें सुरक्षितताका हक है। मातृत्व तथा बचपनको खास मदद और संभाल मिलना चाहिये। . . . . . " संयुक्त राष्ट्र-संघके मानवीय अधिकारोंके घोषणा-पत्रकी अेक धारामें अैसा कहा गया है।

अिस अुत्तम आदर्शको कल्याण-राज्यके — जिसके विषयमें आजकल बहुत कुछ कहा-सुना जा रहा है — आधारके रूपमें स्वीकार किया गया है। राजनीतिक लोग तो कल्याण-राज्यका गुण-गान करते थकते ही नहीं। अुन्हें छोड़ दें, तो अिस विचारधाराको माननेवाले कअी बुद्धिशाली लोग भी, मौजूदा आर्थिक बुराअियोंको कल्याण-राज्य किस तरह दूर कर देगा, अिसके विषयमें बड़े अुत्साहसे चर्चा करते हैं। अुन्हें अिस बातमें कोअी सन्देह नहीं है कि अैसे राज्यकी स्थापनाके द्वारा ही लोगोंकी आर्थिक स्थिति सुधारी जा सकती है और समाजमें प्रचलित असमानताओंको कम किया जा सकता है। संक्षेपमें, अुनका खयाल है कि कल्याण-राज्य अेक नयी (और सचमुच क्रान्तिकारी) समाज-रचनाका आश्वासन देता है, जिसमें सब लोगोंको अमुक अल्पतम जीवन-मानकी गारण्टी रहेगी। वह गोया अेक मानवीय और प्रगतिशील समाजके चित्रकी रूप-रेखा पेश करता है।

अिससे तो कोअी अिनकार नहीं कर सकता कि हरअेकको अुसकी जीवन-आवश्यकताअें प्रदान करनेवाले कल्याण-राज्यकी कल्पना बहुत आकर्षक है। लोग अैसा मानने लगते हैं कि कल्याण-राज्य अुनके सवाल सुलझायेगा और आजके राज्यको कल्याण-राज्यका रूप दे डालना भारी प्रगतिका चिन्ह है। कल्याण-राज्यकी स्थापना करना ही हमारा अुद्देश्य है, अिस बातकी बार-बार घोषणा करके जनताका समर्थन अपने अपने लिअे प्राप्त करनेमें राजनीतिक पक्ष अेक-दूसरेकी होड़ कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टीने भी अपने आवड़ी अधिवेशनमें 'समाजवादी स्वरूपकी समाज-व्यवस्थाके साथ कल्याण-राज्य' की स्थापनाको बहुत स्पष्ट शब्दोंमें अपना अुद्देश्य स्वीकार किया है। चूंकि आज सत्ता अिसी पक्षके पास है अिसलिअे देशकी साधन-सामग्रीके विकासके लिअे योजनाअें अिसी अुद्देश्यको दृष्टिमें रखकर बनायी जा रही हैं। पहली पंचवार्षिक योजना पूरी हो रही है और दूसरी अिससे भी ज्यादा महत्त्वाकांक्षी योजना बनायी जा रही है। अिस दूसरी योजनामें भारी तथा यंत्र-सामग्री बनानेवाले अुद्योगोंकी स्थापना तथा छोटे ग्रामोद्योगोंके विकास पर भी जोर दिया जा रहा है।

कल्याण-राज्यका आदर्श वैसे ठीक है, लेकिन गांधीजीकी सर्वोदय व्यवस्थामें माननेवाले हम लोग सरकारकी नीतियों और कार्यक्रमोंके बारेमें अुदासीन नहीं रह सकते। देशकी साधन-संपत्ति व्यवस्थित ढंगसे और योजनापूर्वक विकसित करनेका प्रयत्न पहली बार हो रहा है और भारत-जैसे अर्ध-विकसित देशमें, जहां बड़े पैमानेवाला अुद्योगीकरण अभी कुछ ज्यादा नहीं हुआ है, सर्वोदयकी व्यवस्थाकी दिशामें प्रयोग करना और कार्य आरंभ करना अधिक आसान है। अन्यथा यदि सर्वोदयमें माननेवाले अपने विचार स्पष्ट शब्दोंमें पेश करनेके बजाय संकल्प-विकल्पकी स्थितिमें बैठे रहेंगे तो जिस समय सरकारकी भारी अुद्योगोंको प्रमुखता देनेवाली महत्त्वाकांक्षी योजना पूरी होगी अुस समय अुन्हें तुरन्त ही मालूम पड़ेगा कि वे सरकारके कार्यक्रमोंके साथ अेकराय नहीं हो सकते। अिसके सिवा जहां देशकी आर्थिक रचना अेक बार भारी तथा बड़े पैमानेवाले अुद्योगोंके आधार पर बनी कि विकेन्द्रित अर्थ-रचनाकी — गांधीजी चाहते थे कि आजाद भारत अपने सवाल हल करनेके लिअे और समृद्ध तथा अुदात्त जीवनकी दिशामें प्रगति करनेके लिअे अर्थ-रचनाकी अिसी पद्धतिको अपनावे — स्थापनाके प्रयत्नमें अनेक कठिनाअियां खड़ी हो जायंगी और अुन पर विजय पाना आसान नहीं होगा और शायद संभव भी नहीं होगा। अगर हम अपनी स्थिति आज अभी स्पष्ट नहीं करते हैं तो हम अेक बड़ा अवसर चूक जायेंगे। क्योंकि कालान्तरमें जब देशकी आर्थिक रचनाकी अिमारत भारी अुद्योगोंकी नींव पर खड़ी की जा चुकेगी, तब सरकारकी नीतिसे असंतुष्ट और हताश सर्वोदयवादी अिने-गिने ही होंगे और अुस समय यदि वे कुछ कहेंगे तो अुन्हें पोथी-पण्डित ही माना जायगा। अुस समय हमारी स्थिति पश्चिमके अुन विचारकों जैसी होगी जो आधुनिक यंत्र-युगकी सिद्धियोंको शंकाकी दृष्टिसे देखते हैं।

सर्वोदयवादियोंको अिस सारी स्थिति पर तत्काल विचार और कार्य करना आरंभ करना चाहिये, अिसका अेक और कारण भी है। वह यह है कि लोगोंके मनमें अेक भ्रम पैदा किया जा रहा है कि कांग्रेस द्वारा परिकल्पित कल्याण-राज्य वही चीज है जिसे गांधीजी सर्वोदय-राज्य कहते थे। सामान्य मनुष्यको अपने कार्यव्यस्त दैनिक जीवनमें न तो अितना समय मिलता है और न अुसे अिसकी रुचि ही है कि वह अिन सवालों पर विचार करे और अपने स्वतंत्र निर्णय पर पहुंचे। अिसलिअे यह और भी जरूरी हो जाता है कि हम अिस बातको स्पष्ट कर दें कि कल्याण-राज्यके सिद्धान्तों और सर्वोदय-राज्यके सिद्धान्तोंमें समानता कहां तक है। अिस लेखमें अिन दो विचारोंकी समानताअें और असमानताअें बतानेका प्रयत्न किया जायगा।

(चालू)

(अंग्रेजीसे) पी० श्रीनिवासाचारी

सर्वोदय

लेखक: गांधीजी; संपा० भारतन् कुमारप्पा

कीमत २–८–० डाकखर्च ०–१२–०

रचनात्मक कार्यक्रम

[चौथी बार]

लेखक: गांधीजी; अनु० काशिनाथ त्रिवेदी

कीमत ०–६–० डाकखर्च ०–३–०

भूदान-यज्ञ

विनोबा भावे

कीमत १–४–० डाकखर्च ०–५–०

सर्वोदयका सिद्धान्त

कीमत ०–१०–० डाकखर्च ०–४–०

नवजीवन प्रकाशन मन्दिर, अहमदाबाद–१४

विषय-सूची

		पृष्ठ
भय, असुरक्षितता और अनुशासनहीनता	मगनभाई देसाई	२६५
सामाजिक खर्च और राज्यसत्ता	मगनभाई देसाई	२६६
आन्ध्रमें विनोबाके तीन दिन	दामोदरदास मूंदड़ा	२६७
भाषाका सवाल	जवाहरलाल नेहरू	२६८
खादी और ग्रामोद्योगोंका अर्थशास्त्र	मगनभाई देसाई	२६९
हाथ-कुटाअीका अुद्योग	वि०	२७०
कल्याण-राज्य बनाम सर्वोदय-राज्य	पी० श्रीनिवासाचारी	२७१

www.vinoba.in